



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1977/ वैशाख 10, 1899

No. 140]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1977/VAISAKHA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April 1977.

G.S.R. 203(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, I, Basappa Danappa Jatti, Vice-President acting as President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Himachal Pradesh cannot be carried on in accordance with the provision of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State,
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State,

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely.—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India,

articles 163 and 164,

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State; article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174, articles 175 to 178 (both inclusive); clause (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196, article 198, clauses (3) and (4) of article 199; articles 200 and 201;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive), the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively;

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State.

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 (Himachal Pradesh Act 18 of 1969), as in force in the State of Himachal Pradesh and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi,
The 30th April, 1977

B. D. JATTI,
Vice-President acting as President.

New Delhi;
The 30th April, 1977.

[No V/11013/3/77-S&P(DV)]
T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Secy.

ORDER

New Delhi, the 30th April 1977

G.S.R. 204(E).—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 30th day of April, 1977, by me under article 356 of the Constitution of India. I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Himachal Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State

New Delhi,
The 30th April, 1977

B. D. JATTI,
Vice-President acting as President.

New Delhi;
The 30th April, 1977.

[No V/11013/3/77-S&P(DV)]
T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Secy.

गृह संत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1977

सा०का०नि० 203 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :

यतः मेरा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति, बसप्पा दानप्पा जत्ती का समाधान हो गया है कि ऐ पी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संविधान' कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं:—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूँ;

(ख) घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियाँ संसद के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और परिणामिक उपबन्ध करता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक या वाछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात् :—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिए गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझू, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उस राज्य के संबन्ध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात् .—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का सबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निदेश करने से है ,

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ,

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्यों का मंत्रियों के बीच आवंटन से है ; अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के पारित किए जाने से है ,

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उपखंड (क) ; अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) ; अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक और अनुच्छेद 180 और 181.

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलनों और भत्तों से है, अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 तथा 196; अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4); अनुच्छेद 200 और 201;

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलनों और भत्तों से है; अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं) , अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक, और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

(iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्वारा विघटित की जानी है ,

(iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निवेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित

न हो, संसद् के प्रति निदेश लगाया जाएगा, और विशिष्टतय अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद् या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा ;

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेंगे और न राष्ट्रपति को इस खंड के उप-खंड (1) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी ;

(V) सविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानों उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या सविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है, और हिमाचल प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1968 (हिमाचल प्रदेश 1969 का अधिनियम 16) जिस रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू है, और साधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 के 10वें) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानों यह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो।

नई दिल्ली
30 अप्रैल, 1977

बसप्पा दानप्पा जत्तो,
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति।

[सं. V 11013/3/77-एस एंड पी (डी-V)]

नई दिल्ली,
30 अप्रैल, 1977

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव।

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1977

सा०का०नि० 204 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है .

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज 1977 को अप्रैल के तीसरे दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या प्रयोज्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षक, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा ही प्रयोज्य होगी ।

नई दिल्ली,;

30 अप्रैल, 1977

बसप्पा दानप्पा जसी,

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति ।

[से० V/11013/3 77-एस एंड पी (डी-V)]

नई दिल्ली;

30 अप्रैल, 1977

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

